गरवी गुजरात

RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 02
अंक : 008
दि. 08.05.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

पटना में मोदी-नीतीश की केमिस्ट्री! पीएम के इशारे पर सम्राट ने नीतीश को बुलाया, फिर मंच पर दिखा याराना

(जीएनएस)।

पटना के गांधी मैदान में आयोजित मंत्रिमंडल विस्तार समारोह में अद्भुत राजनीतिक नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को मंच के केंद्र में बुलवाया। इसके बाद नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के कंधे पकड़कर और मुस्कुराते हुए जिस गर्मजोशी से मुलाकात की। पटनाः बिहार की राजनीति में आज का दिन न केवल नई कैबिनेट के गठन के लिए, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच के मजबूत संबंधों के लिए भी याद किया जाएगा। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आयोजित इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री विशेष तौर पर शामिल हुए। समारोह संपन्न होने के बाद जब मंच पर फोटो सेशन की तैयारी चल रही थी, तब पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच की 'केमिस्ट्री' ने सबका ध्यान खींचा। प्रधानमंत्री ने खुद पहल करते हुए नीतीश कुमार को सम्राट से कहकर अपने पास बुलाया और उसके बाद जो गर्मजोशी दिखी, वो यादगार पल बन गया।

शपथ के मंच पर पीएम मोदी-नीतीश की केमिस्ट्री

दरअसल, बिहार में आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी ने शपथ ली थी। इसके बाद 7 मई को पटना के गांधी मैदान में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पीएम मोदी आज के मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हुए।

पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंच पर गहमागहमी थी। पीएम मोदी के बगल में सीएम सम्राट चौधरी खड़े थे। फोटो सेशन की तैयारी चल रही थी। तभी पीएम मोदी ने सम्राट चौधरी को इशारा किया कि वो नीतीश कुमार को बुलाकर लाएं। फिर सम्राट ने वहां मौजूद किसी को बोला कि नीतीश कुमार को लेकर आइए।

फिर जैसे ही नीतीश कुमार पीएम मोदी के नजदीक आए उन्होंने नीतीश कुमार के हाथ पकड़कर गर्मजोशी दिखाया। दोनों नेताओं ने मुस्कुराकर अभिवादन किया। फोटोग्राफी के दौरान नीतीश कुमार हाथ हिलाकर आभिवादन करते रहे। फिर उन्होंने पीएम मोदी के दोनों कंधों झोर से हिलाकर अपनी गहरी दोस्ती को जताया। इसके बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार आपस में बात करते रहे। बीच-बीच लोगों के अभिवादन भी स्वीकार करते रहे।

बिहार में आज 32 नए

मंत्रियों ने ली शपथ

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मंत्रिपरिषद का गठन के 22 दिनों बाद बृहस्पतिवार को पहला विस्तार किया गया, जिसमें 32 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह पांच पांच मंत्रियों के समूह में संपन्न हुआ।

मंत्रिपरिषद विस्तार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कोटे से मिथिलेश तिवारी, नीतीश मिश्र, रामचंद्र प्रसाद, नंद किशोर राम और केदार गुप्ता को मंत्री बनाया गया। इस विस्तार में पूर्व केंद्रीय मंत्री मंगल पांडेय को जगह नहीं मिली।

गांधी मैदान में बने विशाल पंडाल में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

लोकभवन (राजभवन) परिसर से बाहर, बड़े स्तर पर मंत्री परिषद विस्तार समारोह आयोजित किया गया। भाजपा की अगुवाई में बनी बिहार सरकार के नए मंत्रियों में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश को भी मंत्री परिषद में शामिल किया गया।

मंत्रिपरिषद विस्तार में नीतीश कुमार सरकार के अधिकतर पूर्व मंत्रियों को फिर से स्थान दिया गया है, जबकि कई नये चेहरों को भी मौका मिला है। भाजपा कोटे से विजय कुमार सिन्हा, रामकृपाल यादव, केदार गुप्ता, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, रमा निषाद,दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, प्रमोद चंद्रवंशी, लखविंदर पासवान, संजय टाइगर, इंजीनियर कुमार शैलेन्द्र, नंद किशोर राम, रामचंद्र प्रसाद और अरुण शंकर प्रसाद को मंत्री बनाया गया है।

जदयू कोटे से निशांत कुमार, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, रत्नेश सदा, मदन सहनी, लेसी सिंह, श्वेता गुप्ता, बुलो मंडल, दामोदर रावत, भगवान सिंह कुशवाहा, सुनील कुमार, शीला मंडल और जमा खान को मंत्री बनाया गया है। विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव पहले से मंत्री हैं।

वहीं, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) से संजय सिंह व संजय पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम से संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो से दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं।

प.बंगाल में विधानसभा भंग, ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री नहीं

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर हो गया. कार्यकाल खत्म होते ही राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी, जिसके साथ ही ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री पद भी समाप्त हो गया. इस्तीफे को लेकर जारी सियासी खींचतान के बीच यह फैसला सीधे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ, जिससे बंगाल में 15 साल पुराना सत्ता का अध्याय अचानक खत्म हो गया.

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्यपाल आर.एन. रवि ने विधानसभा को भंग कर दिया है और यह फैसला 7 मई 2026 से लागू हो गया है. इसका सीधा मतलब है कि अब राज्य में न कैबिनेट बची है और न ही ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद पर हैं. इस्तीफे को लेकर चल रही खींचतान के बीच यह बदलाव संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लागू हुआ.

गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 (2)(b) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल किया है. इस

नोटिफिकेशन पर बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला के भी हस्ताक्षर हैं. विधानसभा भंग होने के साथ ही बंगाल में बीते 15 साल से चला आ रहा तृणमूल कांग्रेस का शासन अब खत्म हो गया है.

अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि आखिर ये अनुच्छेद 174(2)(b) क्या है, जिसके दम पर राज्यपाल ने इतना बड़ा फैसला लिया? दरअसल, भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को भंग करने की सबसे बड़ी ताकत देता है. इसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर या फिर सरकार के बहुमत खोने की स्थिति में विधानसभा को समय से पहले भंग कर नए चुनाव या नई सरकार का रास्ता साफ कर सकते हैं. इसमें राज्यपाल को सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त करने की भी शक्ति मिलती है. हालांकि, राज्यपाल को यह सुनिश्चित करना होता है कि विधानसभा के दो सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप न हो. सीधा मतलब यह है कि जब सदन में कोई पार्टी बहुमत साबित न कर पाए या जनादेश बदल जाए, तब राज्यपाल इसी अनुच्छेद का 'हंटर' चलाकर पुरानी व्यवस्था को खत्म करते हैं, जैसा आज बंगाल में देखने को मिला.

प्रधानमंत्री ने बिहार सरकार में नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई दी

प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता द्वारा दिए गए गर्मजोशी भरे स्वागत और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि राज्य के चौतरफा विकास को लेकर उनकी प्रतिबद्धता बिहार को समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उन्होंने सभी से सशक्त बिहार और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करने के लिए मिलकर काम करने का आ'ान किया।

प्रधानमंत्री ने पटना यात्रा के दौरान बिहार की जनता से प्राप्त स्नेह और आशीर्वाद के लिए भी आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि उन्हें मिले हार्दिक स्वागत से वे अभिभूत हैं और उन्होंने

लोगों के समर्थन और उत्साह के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के बीच अभूतपूर्व उत्साह विकास और जनसेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के लिए मजबूत जनसमर्थन को दशार्ता है।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा; 'बिहार की एनडीए सरकार में मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं! मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य के चौतरफा विकास के लिए आपकी प्रतिबद्धता हमारे इस प्रदेश को समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आइए, हम सब मिलकर एक सशक्त बिहार और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करें।'

प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर सशस्त्र बलों को सलाम किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के आज एक वर्ष पूरे होने पर सशस्त्र बलों के साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प को सलाम किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हमला करने की हिम्मत करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया।

श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कड़ी कार्रवाई और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 द्विपक्षीय सहयोग के अगले चरण को गति देगा: डॉ. जितेंद्र सिंह

(जीएनएस)।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री प्रो. फिलिप बैपटिस्ट के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग के बढ़ते दायरे की समीक्षा की गई।

इस वार्ता से भारत-फ्रांस की दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की गहराई का पता चला, जिसमें दोनों पक्षों ने विशेष रूप से उच्च-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की निरंतर गति पर संतोष व्यक्त किया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत-फ्रांस की सहभागिता द्विपक्षीय संबंधों का एक मजबूत स्तंभ बन गई है, जो तकनीकी प्रगति और जन-जन के बीच घनिष्ठ जुड़ाव में योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि 2026 को भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष घोषित किए जाने से उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होता है।

हाल के घटनाक्रमों का जिक्र

करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और प्रमुख फ्रांसीसी संगठनों के बीच संस्थागत साझेदारी को मजबूत करने के बारे में चर्चा की, जिसमें उन्नत सामग्री और डिजिटल विज्ञान में नई पहल के साथ-साथ इस वर्ष शुरू की गई प्रयुक्त गणित और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर संयुक्त पहल भी शामिल है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष सहयोग को लेकर इसरो और सीएनईएस के बीच लंबे समय से चले आ रहे सहयोग के बारे में बताया, जिसमें मेघा-ट्रॉपिक्स और सरल जैसे संयुक्त उपग्रह मिशन और तृष्णा पर चल रहा कार्य शामिल है। उन्होंने फ्रांस में नेविक ग्राउंड स्टेशन के विकास में सहयोग का भी जिक्र किया और भारत के गगनयान मिशन में फ्रांस के समर्थन को स्वीकार किया।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि हाल के सुधारों के बाद भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ है, जिसमें लगभग 400 अंतरिक्ष स्टार्टअप का एक बढ़ता हुआ इकोसिस्टम है और आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत अनुमान हैं, जो दोनों देशों के बीच गहन उद्योग-स्तरीय साझेदारी के नए अवसर पैदा कर रहे हैं।

फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री प्रो. फिलिप बैपटिस्ट ने भारत को अंतरिक्ष और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग का एक प्रमुख और विश्वसनीय भागीदार बताया। इसरो के साथ अपने पूर्व संबंधों को याद करते हुए, उन्होंने सहयोग की मजबूत विरासत पर प्रकाश डाला और पृथ्वी अवलोकन, प्रक्षेपण प्रणालियों और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने में रुचि व्यक्त की।

प्रो. फिलिप बैपटिस्ट ने "स्पेस फॉर ओशन एलायंस" के माध्यम से महासागर संबंधी डेटा साझाकरण में सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव रखा और सीएनईएस तथा भारतीय संस्थानों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का सुझाव दिया। उन्होंने प्रशिक्षण, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोगों और दीर्घकालिक सहयोगात्मक अवसरों सहित मानव अंतरिक्ष उड़ान में सहयोग के विस्तार के लिए तत्परता भी व्यक्त की।

प्रो. बैपटिस्ट ने वैश्विक सहभागिता का जिक्र करते हुए भारत को सितंबर 2026 में पेरिस में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

'बंगाल के बाद अब पंजाब है भाजपा का निशाना', संजय सिंह ने धमाकों को बताया चुनावी रणनीति का हिस्सा

(जीएनएस)।

पंजाब के जालंधर और अमृतसर में हुए बम ब्लास्ट को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव "लूटने" के बाद अब भाजपा का अगला निशाना पंजाब है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में अमन-चैन बिगाड़ने, लोगों के बीच नफरत फैलाने और झगड़े कराने के लिए ही भाजपा "मिशन पंजाब" चला रही है।

गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान संजय सिंह ने कहा कि अमृतसर और जालंधर में हुए बम ब्लास्ट भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आईएसआई के बीच गहरा रिश्ता है और आईएसआई के जरिए देश में ब्लास्ट और अशांति फैलाने का काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा की "नफरती राजनीति" सफल नहीं होगी और अगर राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश की गई तो जनता जवाब देगी। संजय सिंह ने कहा कि बुधवार को पंजाब में दो जगहों पर बम ब्लास्ट हुए और उसके बाद भाजपा नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई। उन्होंने 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हुए मौड़ ब्लास्ट का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि उस समय पंजाब में अकाली दल और भाजपा की सरकार थी और आज तक उस मामले का सच सामने नहीं आया।

उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद भाजपा "मिशन पंजाब" की बात कर रही है। उनके मुताबिक भाजपा का मिशन पंजाब में ब्लास्ट, नफरत और अशांति फैलाना है।

प्रेस वार्ता में संजय सिंह ने पुलवामा हमले और पहलगाम की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलवामा हमले में इस्तेमाल हुआ 350 किलो आरडीएक्स भारत की सीमा में कैसे पहुंचा, इसका जवाब आज तक नहीं मिला।

उन्होंने कहा कि पहलगाम में महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया, ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि वहां से सुरक्षा किसके आदेश पर हटाई गई थी। उनका कहना था कि जम्मू-कश्मीर की कानून व्यवस्था भाजपा के हाथ में है, फिर भी आतंकवादी हमला हो गया और जवाबदेही तय नहीं हुई।

संजय सिंह ने कहा कि पठानकोट आतंकी हमले के बाद जांच के लिए आईएसआई को भारत बुलाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला मोदी सरकार के दौरान हुआ और भाजपा का आईएसआई से "पुराना रिश्ता" रहा है।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे उत्तराखंड, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत

ऋषिकेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुरुवार को उत्तराखंड पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर हेलीपैड पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया।

इसके बाद सीएम योगी का अपने पैतृक गांव पंचूर जाने का कार्यक्रम है। पंचूर में हरि विष्णु पंचदेव मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। समापन कार्यक्रम शुक्रवार को है। योगी आदित्यनाथ शनिवार को वापस लौटेंगे।

'2027 में पंडित जी सपा सरकार बनवाएंगे', अखिलेश यादव ने बता दिया अपने मिशन यूपी का फॉमूर्ला

(जीएनएस)।

लखनऊः देश के 5 राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई को आ गए हैं। 5 राज्यों में 3 में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 5 राज्यों में इंडिया गठबंधन कहीं भी नहीं जीता है। तमिलनाडु से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है। वहीं, विपक्ष के लिए पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा झटका रहा है। ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई हैं। ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री थीं, लेकिन इस बार बीजेपी ने हरा दिया है। अगले साल यूपी में चुनाव होने वाले हैं। इसको देखते हुए अखिलेश यादव अलर्ट मोड पर आ गए हैं।

अखिलेश यादव ने लखनऊ में बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि 2012 में कैसे सपा सरकार बनी थी, वही फामूर्ला 2027 के यूपी चुनाव में लागू करने की बात कही। इसी मंत्र से अखिलेश यादव ने 2027 में सरकार बनाने का दावा किया। अखिलेश

यादव ने कहा कि एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके इतना कहते ही वहां मौजूद लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अकपंडित और बहुत बड़े जानकार ऋषि-मुनि हमारे संपर्क में आए हैं, जब से केदारेश्वर मंदिर बनवा रहा हूं। इसी पार्टी कार्यालय में कल भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आए थे। सच्चाई ये है कि वो आपका मन पढ़ लेते हैं। मेरे अलावा उन्होंने यहां 3 लोगों के इंटरव्यू लिए।

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बस आप उनसे ये नहीं पूछ सकते हैं कि बीजेपी का कौन-कौन उनसे जुड़ा है, लेकिन हमें पता चल गया है। पंडित जी ने मुझसे कहा कि आप जो लिख देंगे, उसे मैं पूरा कर दूंगा। उनकी बात सुनकर मैंने अपने रजिस्टर पर दो बातें लिख दीं। उन्होंने बिना देखे बता दिया कि मैंने क्या लिखा था। मैंने सिर्फ दो ही बातें लिखी थीं कि सपा सरकार बनवाइए और यूपी को खुशहाली के रास्ते पर ले जाइए, जिसे पंडित जी ने एकदम सही बताया, इसलिए हमारे पंडित जी जो कहेंगे, वहीं हम करेंगे। 2012 में उन्होंने सरकार बनवाई थी।

सम्पादकीय

बंगाल की जनता ने तोड़ी लगातार एक ही सरकार को लंबे समय तक बिठाए रखने वाली परंपरा

इस बार के चुनाव में बंगाल की जनता ने लगातार एक ही सरकार को लंबे समय तक बिठाए रखने वाली परंपरा को तोड़ दिया है। 34 साल वाम मोर्चा और 15 साल टीएमसी के बाद जनता ने बता दिया कि सत्ता का लाइसेंस स्थायी नहीं होता। अब ह्यबंगवासीह्न को भ्रष्टाचार मुक्त, हिसा मुक्त, भू-माफिया मुक्त, कटमनी मुक्त, तोला बाज मुक्त, तुष्टिकरण से परे, सिंडिकेट राज मुक्त और अपराध मुक्त बंगाल चाहिए। और इस तरह हुआ बंगाल में तृणमूल सरकार का पतन पमि बंगाल का जनादेश आ चुका है। मतगणना के बाद साफ हो गया कि बंगाल की जनता ने इस बार परंपरा तोड़ दी है। 2011 से लगातार सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस के सामने अब अस्तित्व का संकट है, जबकि भारतीय जनता पाटा पर जनता ने बड़ा जोखिम लेकर भरोसा जताया है। बंगाल के लोगों ने इस बार केवल सरकार बदलने का पैसला नहीं लिया है उन्होंने उस राजनीतिक संस्वृति को भी नकारा है जहां बयानबाजी, तानाशाही और गुंडागदा शासन पर भारी पड़ रही थी और तुष्टिकरण विकास की जगह ले रहा था। इन चुनाव परिणामों की नींव मतदान से महीनों पहले ही पड़ चुकी थी। मुख्यमंत्री ममता बनजा सहित टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं के लगातार गैर-जिम्मेदाराना बयानों ने बंगाल की जनता में गहरा असंतोष पैदा किया। तृणमूल कांग्रेस तब विवादों के घेरे में आ गईं जब मंत्री और वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम ने कोलकाता में एक अखिल भारतीय वुरान प्रतियोगिता के मंच से कहा ह्यजो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए हैं वे दुर्भाग्यशाली हैंह्न और ह्यइस धर्म को गैर-मुसलमानों के बीच पैलाया जाना चाहिएह्न एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता का यह वत्तव्य बंगाल की साझा संस्वृति के विरुद्ध था। दुगार्पूजा और ईंद साथ मनाने वाले बंगाल में हिदू बंगाली समाज ने इसे अपनी अस्मिता पर चोट माना। नाराजगी स्वाभाविक थी। मुख्यमंत्री ममता बनजा ने भी इस आग में घी डाला। एक सभा में उन्होंने कहा, ह्यहम हैं इसलिए आप सब सुरक्षित हैं। अगर हम नहीं रहे, तो एक सेवंड में 12 बजा दिए जाएंगेह्न यह बयान एक विशेष समुदाय को संबोधित करते हुए देखा गया। इसका सीधा संदेश यह गया कि बहुसंख्यक हिदू समाज की सुरक्षा सत्ता की वृपा पर निर्भर है। नतीजा यह हुआ कि हिदू बंगालियों में असुरक्षा की भावना घर कर गईं। पमि बंगाल के फालता में टीएमसी नेता जहांगीर खान और चुनाव आयोग द्वारा नियुत्त यूपी वैडर के आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा के बीच हुईं तकरार ने प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। मतदाताओं को डराने की शिकायत पर जब अजय पाल शर्मा टीएमसी नेता के घर पहुंचे तो जवाब मिला, ह्यअगर अफसर ह्यसिघमह्न हैं, तो हम ह्यपुष्पाह्न हैं, झुकेगा नहीं। हम भाजपा के अफसरों से नहीं डरेंगेह्न एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी से इस तरह का अशोभनीय व्यवहार और उसे ह्यभाजपा का अफसरह्न कहकर खारिज करना बंगाल के ह्यभद्र मानुषह्न को रास नहीं आया। अपनी करतूतों को नजरअंदाज कर उल्टे कानून के रखवाले को धमकाना जनता ने गुंडागदा की खुली छूट माना। कानून-व्यवस्था पहले से ही बड़ा मुद्दा थी, इस घटना ने उसे और धार दे दी। वोटिग से ठीक पहले टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद अभिषेक बनजा ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, ह्यअगर आपमें हिम्मत है तो मतगणना वाले दिन कोलकाता में रहिएगा, फिर हम देखेंगेह्न वे ममता बनजा की चौथी बार सरकार बनने को लेकर आश्वस्त दिखे, पर ह्यखेलाह्न उल्टा हो गया। अभिषेक बनजा के अभद्र बयान से बंगवासी नाराज हो गए। चुनाव के बीच संवैधानिक पद पर बैठे वेंद्रीय मंत्री को इस भाषा में ललकारना मर्यादा का उल्लंघन था। जनता ने इसे अहंकार माना। इसी कड़ी में अनुव्रत मंडल जैसे नेताओं की ह्यबाहुबलीह्न छवि और उनके विवादित बयानों ने भी टीएमसी की छवि को नुकसान पहुंचाया। वुल मिलाकर जनता के बीच यही संदेश गया कि सत्ता सेवा नहीं, धमकी का औजार है। ममता बनजा ने इस बार भी बंगाल की जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ने की भरपूर कोशिश की, पर सफल नहीं हो सकीं। वे एसआईआर, झालमुड़ी, ह्यबाहिरागतह्न यानी बाहरी लोग, वेंद्रीय बलों की तैनाती, बात-बात

उत्तर प्रदेश बनेगा प्रीमियम फल उत्पादन और निर्यात का बड़ा हब

लखनऊ में 'फ्रूट होराइजन 2026' में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की सहभागिता

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने बताया फल निर्यात में भारत को नंबर वन बनाने का रोडमैप

फलों की गुणवत्ता, शेल्फ लाइफ और निर्यात पर सरकार का बड़ा फोकस- केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान

किसानों की आय बढ़ाने को बनेगा फल सेक्टर का एक्शन प्लान- श्री शिवराज सिंह चौहान

गुणवत्ता से ग्लोबल मार्केट तक: फलों पर राज्य के साथ मिलकर केंद्र सरकार का बड़ा विजन

(जीएनएस)।

लखनऊ के आईसीएआर-केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान (CISH) में आयोजित 'फ्रूट होराइजन 2026' में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि अब केवल ज्यादा उत्पादन से बात नहीं बनेगी, बल्कि भारत को वैश्विक फल बाजार में मजबूत पहचान दिलाने के लिए गुणवत्ता, शेल्फ लाइफ, प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और निर्यात मानकों पर गंभीरता से काम करना होगा। उन्होंने जोर दिया कि खेती को खेत तक सीमित नहीं रखा जा सकता; अब उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, बाजार और निर्यात तक पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करना समय की मांग है।

अब फोकस सिर्फ उत्पादन नहीं, गुणवत्ता पर भी, इस महत्वपूर्ण आयोजन में किसानों के साथ ही फल उत्पादन तथा निर्यात सहित इसके कारोबार से जुड़े सभी हितधारकों के साथ सीधा संवाद करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत अगर दुनिया के फल बाजार में आगे बढ़ना चाहता है, तो फलों की गुणवत्ता सुधारना सबसे जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शेल्फ लाइफ बढ़ाने, निर्यात के दौरान गुणवत्ता बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन करने पर अब विशेष ध्यान देना होगा।

किसानों की आय बढ़ाने को बनेगी टास्क फोर्स, कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि आईसीएआर के वैज्ञानिक संस्थान, निर्यातक, एपीडा और अन्य संबंधित एजेंसियां मिलकर एक टास्क फोर्स बनाएंगी। यह टास्क फोर्स उत्पादकों और निर्यातकों की समस्याओं का समाधान करने तथा एक प्रभावी और समयबद्ध एक्शन प्लान तैयार करने का काम करेगी, ताकि किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।

यूपी को मिलेगा क्लीन प्लांट मिशन का बड़ा लाभ, केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों की जरूरतों को देखते हुए भारत सरकार ने क्लीन प्लांटिंग मैटेरियल कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से मजबूत बनाने का फैसला किया है। इसी क्रम में उक्त्रल, लखनऊ में आधुनिक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जहां आम, अमरूद, लीची और एवोकाडो जैसी फल फसलों के लिए रोगमुक्त और नस्ल-शुद्ध पौध सामग्री तैयार और संरक्षित की जाएगी।

जीरो रिजेक्शन और प्रीमियम क्वालिटी पर जोर, श्री चौहान ने कहा कि भारत को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना है तो 'जीरो रिजेक्शन' और प्रीमियम क्वालिटी वाले फलों के उत्पादन पर खास ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, बेहतर पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन, पैकहाउस, प्रसंस्करण सुविधाएं और निर्यात के लिए व्यावहारिक एसओपी तैयार करके भारतीय बागवानी क्षेत्र को नई ऊंचाई दी जा सकती है।

एफपीओ, क्लस्टर और निर्यात ढांचे से बदलेगी तस्वीर, केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने छोटे किसानों को बेहतर बाजार और निर्यात से जोड़ने में एफपीओ, एफपीसी और स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में यह भी रेखांकित किया गया कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कई निर्यातोन्मुख क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में आधुनिक रेडिएशन तथा इंटीग्रेटेड पोस्ट-हार्वेस्ट सुविधाओं, खासकर जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी पहल, को आगे बढ़ाना इस दिशा में अहम कदम होगा।

तमिलनाडुः राज्यपाल ने कहा–विजय की टीवीके बहुमत साबित करे, ऐसे में राजभवन क्या कर सकता है और क्या नहीं

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के बाद चेन्नई की राजनीतिक हलचल अब चुनावी मैदान से निकलकर राजभवन तक पहुंच गई है. अभिनेता-राजनेता विजय की तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन 118 सीटों के बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई.

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के नेतृत्व वाला गठबंधन 73 सीटों पर है, जबकि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) गठबंधन के पास 53 सीटें हैं. किसी एक पार्टी या गठबंधन को साफ बहुमत नहीं मिलने का मतलब है कि सरकार गठन का रास्ता अब गठबंधन बनाने और राज्यपाल की भूमिका पर निर्भर करेगा.

विजय की टीवीके ने औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने अभी तक कोई अंतिम फैसला घोषित नहीं किया है.

संविधान का अनुच्छेद 164 प्रक्रिया को विस्तार से नहीं बताता, इसमें सिर्फ इतना कहा गया है: ह्यमुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे.ह्न यानी मुख्यमंत्री नियुक्त करने की प्रक्रिया संवैधानिक परंपराओं, राजनीतिक परंपराओं और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के आधार पर तय होती है.

अनुच्छेद और पुराने फैसले

संविधान सरकार गठन में राज्यपाल को अहम भूमिका देता है, लेकिन उनकी शक्तियों की भी सीमाएं हैं. अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, सिवाय उन मामलों के जहां संविधान उन्हें विशेष विवेकाधिकार देता है.

अनुच्छेद 164 राज्यपाल को मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 174 के तहत वह विधानसभा बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं या भंग कर सकते हैं. अनुच्छेद 356 तब लागू होता है जब सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पाती और राष्ट्रपति शासन की जरूरत पड़ती है.

समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि राज्यपाल की शक्तियां असीमित नहीं हैं और उन्हें

लोकतांत्रिक परंपराओं के भीतर रहकर काम करना होगा. अदालत ने यह भी कहा है कि राज्यपाल के निजी फैसलों को कानूनी सुरक्षा हो सकती है, लेकिन उनके आधिकारिक फैसलों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है.

एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1994) मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने कहा था कि बहुमत साबित करने का एकमात्र सही तरीका विधानसभा में फ्लोर टेस्ट है. राज्यपाल की निजी राय इससे ऊपर नहीं हो सकती. अदालत ने यह भी कहा कि अगर स्थिर बहुमत बनने की संभावना हो, तो राष्ट्रपति शासन लगाना असंवैधानिक होगा.

रामेश्वर प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2006) मामले में कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत काम करना चाहिए. विधानसभा बुलाए बिना उसे भंग करना विवेकाधिकार का गलत इस्तेमाल माना जाएगा.

नबम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर (2016) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की शक्तियां पूरी तरह निरंकुश नहीं हैं और उन्हें संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर रहकर काम करना होगा, किसी राजनीतिक खिलाड़ी की तरह नहीं.

सरकार ने 1983 में केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सरकारिया आयोग बनाया था. आयोग की 1988 की रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यपाल को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए और उनका पद राजनीतिक नहीं दिखना चाहिए.

राज्यपाल के पास क्या विकल्प हैं

परंपरा के मुताबिक सबसे पहले सबसे बड़ी पार्टी यानी इस मामले में टीवीके को सरकार बनाने के लिए बुलाया जा सकता है ताकि वह विधानसभा में बहुमत साबित करे. इसका मतलब होगा कि विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए और फिर उन्हें तय समय के भीतर विधानसभा में बहुमत साबित करना पड़े. त्रिशंकु विधानसभा में यही सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है और इसे एस.आर. बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट का समर्थन भी मिला है.

रामेश्वर प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा थाः 'संविधान राज्यपाल से उम्मीद करता है कि चुनाव के बाद जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली लोकप्रिय सरकार बनाने की हर संभव कोशिश की जाए.'

राज्यपाल टीवीके से दूसरे दलों के समर्थन पत्र भी मांग सकते हैं, जिससे उनका आंकड़ा 118 तक पहुंच सके. यही नियम किसी संभावित डीएमके-एआईएडीएमके गठबंधन पर भी लागू होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट टालने की कोशिशों के खिलाफ भी चेतावनी दी है. एस.आर. बोम्मई मामले में कोर्ट ने कहा था, 'सरकार की ताकत का आकलन किसी व्यक्ति की निजी राय का विषय नहीं है, चाहे वह राज्यपाल हो या राष्ट्रपति. इसे विधानसभा में सार्वजनिक रूप से साबित किया जाना चाहिए.'

नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रमः सीएम योगी ने सुनाई मूक-बधिर खुशी की कहानी, बोले- दिव्यांगों को बस सही अवसर की तलाश

(जीएनएस)।

लखनऊ/कानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान कानपुर की मूक-बधिर बच्ची 'खुशी' की भावुक और प्रेरणादायक कहानी साझा कर पूरे सभागार को भावुक कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर दिव्यांगजन में प्रतिभा होती है, आवश्यकता केवल सही अवसर, संवेदना और सहयोग की है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले कानपुर की एक बच्ची, जो न बोल सकती थी और न सुन सकती थी, सिर्फ उनसे मिलने और अपने हाथों से बनाया चित्र भेंट करने के लिए अकेले कानपुर से लखनऊ पहुंच गई थी। इलाज के बाद आज वह बच्ची सुन भी रही है, बोल भी रही है और सामान्य जीवन की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, 'मुझे याद है कानपुर की एक बिटिया की कहानी। एक दिन वह बिना किसी को बताए कानपुर से पैदल लखनऊ आ गई। विधान भवन के सामने वह चुपचाप बैठ गई। वह न बोल सकती थी, न सुन सकती थी। उसने अपने हाथ से मेरा एक छोटा सा चित्र बनाकर सामने रख लिया था।' मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के प्रशिक्षित शिक्षकों ने इशारों में उससे संवाद कर उसका परिवार ढूंढा और उसे वापस कानपुर भेजा। बाद में जब उन्हें इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने बच्ची को दोबारा बुलाकर उसके इलाज की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए।

दरअसल, कानपुर की रहने वाली खुशी नवंबर 2025 में बिना बताए घर से निकलकर लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हुए लखनऊ पहुंच गई थी। विधान भवन के बाहर रोते हुए मिलने पर पुलिस उसे सुरक्षित थाने ले गई। जांच और चिकित्सकीय परीक्षण में सामने आया कि बच्ची को सुनने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की आवश्यकता है। इस ऑपरेशन पर लगभग छह से सात लाख रुपये का खर्च आना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग और एक फाउंडेशन के सहयोग से उसके इलाज की पूरी व्यवस्था कराई गई।

26 जनवरी 2026 को खुशी का कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। अब खुशी आवाजें सुन पा रही है और उसने टूटे-फूटे शब्दों में बोलना भी शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उसके मुंह से निकले पहले शब्द थे- 'थैंक यू योगी जी।'

डॉक्टरों के अनुसार नियमित स्पीच थैरेपी और अभ्यास के बाद आने वाले कुछ महीनों में उसकी बोलने की क्षमता और बेहतर होगी तथा एक वर्ष के भीतर वह सामान्य बच्चों की तरह बातचीत कर सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि अगर हम दिव्यांगजनों के साथ भेदभाव करते हैं तो यह अन्याय है। हर व्यक्ति में प्रतिभा होती है, बस सही अवसर और सहयोग चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि ऑपरेशन के बाद खुशी ने सबसे पहले उस पुलिस इंस्पेक्टर का चित्र बनाकर उन्हें भेंट किया, जिन्होंने लखनऊ में उसकी मदद की थी। उन्होंने कहा कि कृतज्ञता का यह भाव समाज को संवेदनशील बनाने की प्रेरणा देता है। खुशी की कहानी इन्हीं प्रयासों का एक जीवंत उदाहरण बनकर सामने आई है।

तमिलनाडु में भाजपा एक सीट पर क्यों हुई ढेर? वोट शेयर भी गिरा, क्या भारी पड़ा अन्नामलाई फैक्टर?

(जीएनएस)।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने राज्य की राजनीति में कई बड़े उलटफेर किए, लेकिन इखढ के 'दक्षिण विजय' के दावों पर पानी फेर दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने अकेले दम पर 11.24% वोट शेयर हासिल कर राज्य में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, वहीं 2026 विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर गिरकर करीब 3% तक सिमट गया।

इतना ही नहीं, 27 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी केवल एक सीट जीत सकी। यह गिरावट सिर्फ चुनावी आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने तमिलनाडु में भाजपा की रणनीति, गठबंधन के फैसलों और अन्नामलाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विस्तार से पढें हार की पूरी इनसाइड स्टोरी

2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए तमिलनाडु में एक मोरल विक्ट्री की तरह देखा गया था। पार्टी ने द्रविड़ दलों उटड और अक्अउटड से अलग होकर चुनाव लड़ा था और 11% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। उस समय बीजेपी ने खुद को राज्य में तीसरी राजनीतिक ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। उस प्रदर्शन के बाद माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी पहले से ज्यादा आक्रामक तरीके से मैदान में उतरेगी। लेकिन परिणाम इसके बिल्कुल उलट रहे।

2024 की 'प्रगति' का 2026 में 'पतन' होने के पीछे कई प्रमुख कारण रहेः

इस बार भाजपा, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा थी। सूत्रों का कहना है कि अन्नाद्रमुक ने भाजपा को वे 27 सीटें दीं, जहां या तो द्रविड़ दलों का गढ़ था या जहां भाजपा की जमानत बचाना भी मुश्किल था। खुद के दम पर लड़ने के बजाय गठबंधन में जूनियर पार्टनर बनने से भाजपा का अपना स्वतंत्र वोट बैंक बिखर गया।

बिहार शपथ ग्रहण में वंदे मातरम् को भूल सीधे बजाया राष्ट्रगान, नए नियम का क्या हुआ?

(जीएनएस)।

पटना के गांधी मैदान में गुरुवार 7 मई 2026 को आयोजित बिहार की नई ठऊअ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह राजनीतिक तौर पर जितना बड़ा था, उतना ही एक प्रोटोकॉल विवाद की वजह से भी चर्चा में आ गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत 32 नेताओं के शपथ लेने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद थे।

लेकिन बिहार मंत्रिमडल विस्तार का समारोह शुरू होते ही सीधे राष्ट्रगान 'जन गण मन' बजा दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे, क्योंकि कुछ महीने पहले ही में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से जारी दिशा-निदेशों में कहा गया था कि सरकारी कार्यक्रमों में अगर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों हों तो शुरूआत 'वंदे मातरम्' से होगी।

गांधी मैदान में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही थीं। मंच पर ठऊअ के तमाम बड़े नेता मौजूद थे और हजारों समर्थक मैदान में पहुंचे थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, राष्ट्रगान बजा और सभी लोग सम्मान में खड़े हो गए। लेकिन कुछ ही देर बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि तय प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं हुआ।

केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने फरवरी 2026 में सरकारी कार्यक्रमों को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि जहां राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों बजाए जाएं, वहां कार्यक्रम की शुरूआत 'वंदे मातरम्' से होगी और समापन राष्ट्रगान से किया जाएगा। इसमें वंदे मातरम के 6 स्टेनजा बजाने की बात भी कही गई थी।

नए नियमों के मुताबिक अब बड़े सरकारी कार्यक्रमों, राज्यपाल और राष्ट्रपति के आगमन समारोह, ध्वजारोहण और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों में 'वंदे मातरम्' का पूरा छह अंतरों वाला संस्करण बजाना अनिवार्य किया गया था, जिसकी अवधि करीब 3 मिनट 10 सेकंड है।

आईपीएल में ई-सिगरेट और गर्लफ्रेंड मामलों पर शिकंजा कसने की तैयारी, एक्शन मोड में आई बीसीसीआई का बड़ा ऐलान

(जीएनएस)।

आईपीएल 2026 के दौरान मैदान के बाहर घट रही घटनाओं ने बीसीसीआई (इउउक) की चिंता बढ़ा दी है। खिलाड़ियों के साथ अनधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही और होटल रूम्स में बाहरी लोगों के प्रवेश के मामलों को देखते हुए बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अब नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

बोर्ड ने अब कुछ कड़े नियम बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। अब यह क्रिकेट लीग कम और अय्याशी का अड्डा ज्यासा नजर आ रही है। इसे देखते हुए बोर्ड ने अब सख्ती से पेश आने की योजना बनाई है। देवजीत सैकिया ने कई अहम बातों का जिक्र किया है।

रक्षा प्रोटोकॉल में चूकः सैकिया ने कहा कि टीम के सदस्यों के साथ कई ऐसे अनधिकृत लोग घूम रहे हैं, जिनके पास अनुमति नहीं है। यह सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा जोखिम है।

होटल और रूम एंट्री पर रोकः बोर्ड के संज्ञान में आया है कि बाहरी लोग खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के कमरों तक पहुंच रहे हैं। देवजीत सैकिया के अनुसार यह हमारे एंटी-करप्शन प्रोटोकॉल के पूरी तरह खिलाफ है।

अधिकारियों का हस्तक्षेपः केवल खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि टीम मालिकों और अधिकारियों द्वारा भी प्रतिबंधित क्षेत्रों में खिलाड़ियों से मेल-जोल बढ़ाने के मामले सामने आए हैं।

नियमों का उदारीकरणः बोर्ड ने माना है कि पिछले कुछ समय में नियमों के पालन में ढिलाई बरती गई है, जिसे अब तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है।

देवजीत सैकिया ने घोषणा की है कि बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल मिलकर एक विस्तृत एडवाइजरी जारी करेंगे। यह एडवाइजरी सभी फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों के लिए लक्ष्मण रेखा की तरह होगी। उन्होंने कहा कि एडवाइजरी का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद यदि कोई भी उल्लंघन पाया जाता है, तो बीसीसीआई और आईपीएल कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करेंगे।

गौरतलब है कि प्लेयर्स को खुलेआम गर्लफ्रेंड्स के साथ होटल में देखा जाता है। टीम बस में भी ऐसा हो रहा है। इसके अलावा खुलेआम ई-सिगरेट और अन्य गतिविधियां देखी जा रही है। यह एक छपरी क्रिकेट लीग नजर आ रही है।

डिस्को, डेटिंग ऐप और खौफनाक ट्विस्ट, 'बंदर' में दिखेगा बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार

बॉबी देओल पिछले कुछ समय से लगातार अपने दमदार किरदारों की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। 'एनिमल' और 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीतने के बाद अब बॉबी देओल बिल्कुल अलग अंदाज में बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। उनकी नई फिल्म 'बंदर' का

टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है।

आपको बता दें कि फिल्म 'बंदर' का दमदार टीजर आज यानी 7 मई 2026 (गुरवार) को रिलीज किया गया है। इस फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है और पहली बार बॉबी देओल उनके साथ काम कर रहे हैं।

टीजर देखकर साफ पता चल रहा है कि ये फिल्म आम बॉलीवुड मूवीज से काफी अलग होने वाली है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

'कहां के रहने वाले हो? काम के पैसे मिल रहे हैं ना', मजदूरों से मिले सीएम योगी, पूछा हालचाल और खिंचवाई फोटो

(जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक और रूप दिखा, जब वह मजदूरों से मुखातिब हुए। मजदूरों का हाल-चाल जानने के साथ ही उन्हें अपने पास बुलाकर उनके साथ बड़े प्रेम से फोटो खिंचवाई।

(जीएनएस)।

गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संवेदनशीलता एक बार फिर देखने को मिली। जब मंगलवार को वह एक कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे और वहां मौजूद मजदूरों को देखकर उनसे पूछा, कहां के रहने वाले हो? काम के पैसे समय से मिल रहे हैं ना। मजदूरों ने हां में सर हिलाया, फिर सीएम ने पूछा फोटो खिंचानी है तो आओ, जैसे ही मजदूरों ने सीएम के मुंह से यह सुना

तत्काल उनके पास पहुंचे और मुख्यमंत्री के साथ खुशी-खुशी ग्रुप फोटो खिंचवाई। यह देख उपस्थित लोग भी मुख्यमंत्री की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सके।

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर छोटे बच्चों और जानवरों को बुलाते और कुछ करते दिख जाते हैं तो वहीं आम लोगों से मिलते जुलते और संवाद करते भी दिखाई देते हैं। इस संदर्भ में उनकी कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। मामला मंगलवार को एक कोई पुलिया के उद्घाटन समारोह के दौरान दिखा, जब मजदूरों को काम करते देख उनका हाल-चाल जानने के साथ ही उनके साथ साथ फोटो खिंचाई। इस दौरान सांसद रवि किशन, मेयर मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह एवं गोरखपुर विधानसभा की कई विधानसभाओं के विधायक सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को इतने नजदीक से देखने और उनके साथ फोटो खींचवाने के बाद मजदूरों के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह और खुशी देखी गई।

सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला सफाईकर्मी गिरफ्तार, सगाई टूटने पर युवक को फंसाने के लिए की थी साजिश

(जीएनएस)।

मऊआइमा (प्रयागराज)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने व बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को दबोच लिया गया है। गुरुवार शाम प्रयागराज के मऊआइमा थाने की पुलिस ने धमकी देने के आरोपित शाहजहांपुर के जलालाबाद निवासी नितेश कटियार पुत्र सुरेंद्र कटियार को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त शाहजहांपुर नगर निगम में सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत है।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि सगाई टूटने के बाद उसने मऊआइमा निवासी पवन चौरसिया को फंसाने के लिए वाट्सएप पर अभद्र टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। बताया गया है मऊआइमा थाना क्षेत्र के बरई निवासी पवन कुमार चौरसिया के वाट्सएप नंबर से मुख्यमंत्री के खिलाफ एक

विवादित और धमकी भरा पोस्ट प्रसारित हुआ था।

इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और फिर मोबाइल नंबर के आधार पर पवन को उठा लिया। इंजीनियर पवन कुमार ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी बहन की शादी के लिए मेट्रीमोनियल वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाई थी। इसी दौरान शाहजहांपुर निवासी नितेश कटियार से रिश्ता तय हुआ। हालांकि बाद में पवन के परिवार वालों ने शादी नहीं करने की बात कही, जिसको लेकर पवन और नितेश के बीच विवाद हुआ था।

रिश्ता टूटने से नाराज होकर नितेश ने पवन को फंसाने की योजना बनाई और वाट्सएप पर टिप्पणी करते हुए धमकी दी थी। उसमें पवन का नंबर टैग किया था। तब पुलिस ने पवन की तहरीर पर केस दर्ज किया। इंस्पेक्टर मऊआइमा राममूर्ति यादव ने बताया कि धमकी देने के आरोपित सफाईकर्मी नितेश को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

हुमायूं कबीर क्या बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद अब बनवाएंगे बाबरी मस्जिद?

,

पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुमायूं कबीर विधानसभा चुनाव के पहले से ही जमकर चर्चा में हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने का प्रण लेने के बाद तृणमूल कांग्रेस से निलंबित किए गए इस नेता ने अपनी नवगठित आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के टिकट पर रेजीनगर और नौदा, दोनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की।

अब राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने जा रही है तब सवाल उठ रहा है कि हुमायुं कबीर क्या करेंगे। उनकी आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) पार्टी नवगठित भाजपा सरकार के समर्थन करेगी? या मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का वादा पूरा करेगी? आइए जानते हैं हुमायूं कबीर की क्या है प्लानिंग?

हुमायूं कबीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, " बंगाल बिधानसभा में मैं विपक्ष में बैठूंगा। भाजपा को अधिक सीटें मिल गई है मेरे ख्याल में था कि वो बहुमत हासिल नहीं कर पाएंगे। मेरा स्टैंड वैसा ही रहेगा और मैं विपक्ष में बैठूंगा। मैं अपने जिला और क्षेत्र के लिए काम करूंगा और अगर सरकार कोई गलत काम करती है, तो मैं लोगों को बताऊंगा कि भाजपा क्या गलत कर रही है, ताकि अगले चुनाव में लोग उनके खिलाफ वोट करें।"

मस्जिद निर्माण पर कबीर ने कहा, "ट्रस्ट का जमीन खरीदकर मस्जिद बना रहे हैं, तो कौन रोकेगा।" उन्होंने यह भी कहा, "कोई रोकना चाहेगा, तो संघर्ष होगा। मैं किसी के घर में नहीं घुसूंगा, किसी को मारने नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझपर कोई हाथ उठाएगा, तो क्या मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा क्या?"

दो सीटों पर जीत के बाद क्या बोले हुमायूं? जीत के बाद कबीर ने कहा, "मुर्शिदाबाद के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मेरे साथ हुए अन्याय और ममता बनर्जी सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे भेदभाव का जवाब दिया।" उन्होंने कहा कि चार महीने पहले पार्टी स्थापित होने के कारण यह जीत अधिक हौसला बढ़ाने वाली है।

ओवैसी की पार्टी से हुमायूं ने क्यों तोड़ा गठबंधन? बंगाल चुनाव से पहले अखवढ और असदुद्दीन ओवैसी की अक्टक्ट ने गठबंधन किया था, लेकिन बाद में अक्टक्ट ने किनारा कर लिया। इसकी वजह एक वायरल वीडियो था जिसमें कथित तौर पर कबीर को भाजपा नेताओं से अपनी नजदीकियों की बात करते देखा गया था।

हुमायूं जहा बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते हैं वहां भाजपा जीती या हारी? हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद बनाने का काम शुरू किया था। 4 मई 2026 को घोषित नतीजों में भाजपा ने यह सीट जीती, जहां उसके उम्मीदवार भरत कुमार झावर 13,000 से अधिक मतों से विजयी हुए। कबीर की पार्टी इस सीट पर तीसरे स्थान पर रही। वहीं टीएमसी दूसरे स्थान पर रही।

हुमायूं कबीर ने रेजिनगर सीट पर भाजपा के बापन घोष को 58 हजार से ज्यादा वोटों से हराकर 1,23,536 मत हासिल किए। नौदा सीट पर भी कबीर ने भाजपा के राणा मंडल को 27,943 वोटों से मात दी और 86,463 वोट पाए।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) : 8 मई से शुरू होगा समर थिएटर फेस्टिवल, 38 दिनों में होगा 10 नाटक का

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) रंगमंडल 08 मई से 14 जून 2026 तक अपना वार्षिक ग्रीष्मकालीन रंग महोत्सव आयोजित करने जा रही है। 38 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न शैलियों और रंग-रूपों के 10 नाटकों की कुल 26 प्रस्तुतियां होंगी। महोत्सव का उद्घाटन रंगमंडल की नवीनतम प्रस्तुति 'अक्स तमाशा' से होगा, जिसका निर्देशन प्रख्यात रंगनिर्देशक भानू भारती ने किया है। इसकी घोषणा आज एनएसडी परिसर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में की गई।

इस अवसर पर एनएसडी के निदेशक श्री चित्तरंजन त्रिपाठी ने कहा, 'भारत रंग महोत्सव 2026 की अभूतपूर्व सफलता के बाद एनएसडी समर थिएटर फेस्टिवल रंगप्रेमियों के

लिए एक और महत्वपूर्ण रंगोत्सव है । हमारे कलाकारों द्वारा नई सृजनात्मक ऊर्जा के साथ प्रस्तुत किए जा रहे 10 चर्चित नाटकों के माध्यम से दिल्ली का सांस्कृतिक वातावरण और अधिक ऊजार्वान होने जा रहा है । हमें आशा है कि दर्शक इसे भी पिछले वर्ष की तरह सफल बनाएंगे।'

उद्घाटन नाटक 'अक्स तमाशा' ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नाटककार चंद्रशेखर बी. कम्बार के प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक 'सीरी सिम्पिगे' का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अनुवाद वरिष्ठ रंगकर्मी प्रो. राम गोपाल बजाज ने किया है । यह नाटक लोककथा जैसी शैली के माध्यम से भ्रम और सत्य की पड़ताल करता है तथा जुड़वां पात्रों के माध्यम से अपने विषयों को व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। अनुष्ठानिक तत्वों और समकालीन रंगभाषा के मेल से यह आधुनिक दर्शकों तक जटिल विचारों को प्रभावशाली ढंग से पहुंचाता है।

महोत्सव में प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य नाटकों में 'बायेन', 'ताजमहल का टेंडर', 'बंदी गली का आखिरी मकान', 'माई री मैं का से कहूँ', 'तमस', 'अंधा युग', 'बाबूजी', 'आधे अधूरे' तथा 'समुद्र मंथन' शामिल हैं, दर्शक इन प्रस्तुतियों के टिकट ऑनलाइन BookMyShow के वेब पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं।

कौन है वो सपा नेता? 70 की उम्र में 20 साल की लड़की से किया चौथा निकाह, 11 बच्चों का है बाप! दूसरी पत्नी की शिकायत पर होगी हो रही पुलिस जांच

दिल्ली-एनसीआर के गाजियाबाद में कैला भट्टा इलाके से निकला यह मामला अब सनसनी का केंद्र बन गया है। समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और दो बार के पूर्व पार्षद 70 वर्षीय हाजी खलील पर 20 वर्षीय युवती यासमीन से चौथा निकाह करने का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाली खुद उनकी दूसरी पत्नी नाजरीन हैं, जिन्होंने 5 मई को गाजियाबाद कमिश्नर कार्यालय में लिखित शिकायत देकर पूरे प्रकरण को सार्वजनिक कर दिया।

नाजरीन का आरोप बेहद गंभीर है। उनका कहना है कि हाजी खलील की आदत बन गई है कि निकाह करना, और उसके बाद हर पत्नी से बच्चे पैदा करना और फिर कुछ समय बाद उन्हें छोड़ देना या घर से निकाल देना।

उन्होंने कमिश्नर को बताया कि 1991-98 के आसपास जब उनका निकाह हुआ था, तब हाजी खलील ने अपनी पहली शादी और उससे हुए 8 बच्चों की कोई जानकारी नहीं दी थी। नाजरीन से उनके तीन बच्चे हैं, दो बेटियां और एक बेटा। तीसरा निकाह 2010 में किया गया, लेकिन संतान न होने पर उस पत्नी को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया गया। अब चौथा निकाह 20 वर्षीय यासमीन (जो स्कूल की छात्रा थीं और हाजी खलील वहां मैनेजर थे) से कर लिया गया है।

नाजरीन का सबसे बड़ा आरोप 50 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर है। उनका दावा है कि हाजी खलील अब ज्यादातर प्रॉपर्टी चौथी पत्नी यासमीन के नाम ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहे हैं। जब नाजरीन ने विरोध किया तो उन्हें और उनके बेटे को घर से निकाल दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई।

4 मई को नाजरीन अपनी बेटियों और बेटे के साथ कैला भट्टा की एक दुकान पर पहुंचीं, जिसे हाजी खलील ने सालों पहले अपने बेटे राशिद के नाम कर रखा था। नाजरीन ने दुकान से राशिद को बाहर निकालकर ताला लगा दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया। राशिद ने कागजात दिखाए, लेकिन नाजरीन कोई दस्तावेज नहीं दे सकीं। इसके बाद 5 मई को उन्होंने कमिश्नर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। एडिशनल पुलिस कमिश्नर जयकरन नैय्यर ने जांच का आश्वासन दिया है।

हाजी खलील ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि नाजरीन उनकी पत्नी नहीं, बल्कि उनके बड़े भाई की पत्नी थीं, जिनकी 2002 में मौत हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने केवल दो निकाह किए हैं, पहली पत्नी से 8 बच्चे और दूसरी से 3 बच्चे। पूरा मामला नाजरीन की संपत्ति हड़पने की चाल है और पुराना पारिवारिक विवाद कोर्ट में चल रहा है। हाजी खलील सपा के पुराने चेहरे हैं। उन्होंने 1995 और 2000 में इस्लामनगर वार्ड से सपा टिकट पर पार्षद का चुनाव जीता था। लेकिन उनके नाम पर नगर निगम की 30 करोड़ रुपये की जमीन पर अवैध कब्जे का पुराना आरोप भी है।

आईपीएल का रोमांच के बीच क्रिकेट प्रेमियों के लिए असली खुशखबरी दिल्ली में आधी रात के बाद भी दौड़ेगी मेट्रो!

(जीएनएस)।

8 मई को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल का रोमांच चरम पर होगा, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए असली खुशखबरी दिल्ली मेट्रो की ओर से आई है। मैच के बाद घर वापसी की चिंता को दूर करते हुए उबर ने 'मिडनाइट गिफ्ट' दिया है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (DC vs KKR) के मुकाबले को देखते हुए अपनी सेवाओं में विस्तार किया है।

मेट्रो प्रशासन ने सभी लाइनों पर आखिरी ट्रेन के समय को बढ़ा दिया है ताकि आधी रात को मैच खत्म होने के बाद दर्शकों को कैब या ऑटो के लिए परेशान न होना पड़े। DMRC ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव केवल कल यानि 8 मई के लिए है और मैच के समापन समय को देखते हुए टाइमिंग में थोड़ा और बदलाव भी रखा जा सकता है। आइए जानतें हैं इस विशेष व्यवस्था से दिल्लीवासियों को कितनी राहत मिलेगी।

दिल्ली मेट्रो की नई टाइमिंग :

DMRC द्वारा जारी चार्ट के अनुसार, 12 घंटे वाले (AM/PM) फॉर्मेट में आखिरी मेट्रो का समय इस प्रकार है:

येलो लाइनः समयपुर बादली के लिए रात 12 बजकर 20 मिनट पर और मिलेनियम सिटी सेंटर के लिए रात 11 बजकर 45 मिनट पर।

ब्लू लाइनः द्वारका सेक्टर-21 के लिए रात 12:00 बजे, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए रात 11 बजकर 35 मिनट और वैशाली के लिए रात 11 बजकर 45 मिनट पर।

ग्रीन लाइनः कीर्ति नगर और इंदरलोक के लिए आखिरी मेट्रो देर रात 1:00 बजे मिलेगी।

वॉयलेट लाइनः कश्मीरी गेट के लिए रात 11 बजकर 20 मिनट और राजा नाहर सिंह के लिए रात 12 बजकर 25 मिनट पर।

अपग्रेडेड यात्री आरक्षण प्रणाली (पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम) में अगस्त से रेलगाड़ियों की होगी शिफ्टिंग

(जीएनएस)।

आज रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में 40 साल पुरानी आरक्षण प्रणाली में अपग्रेडेड सिस्टम पर गाड़ियों की शिफ्टिंग होते समय यात्रियों को परेशानी न हो इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बैठक में रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना और रवनीत सिंह बिट्टू भी उपस्थित थे।

1986 में शुरू हुई इस प्रणाली में पिछले 40 साल में कई छोटे बदलाव किए गए। लेकिन अब इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया है । अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर इसके क्षमता का विस्तार किया गया है ।

रेल आरक्षण प्रणाली ने कई महत्वपूर्ण पड़ाव देखे हैं। वर्ष 2002 में भारतीय रेलवे ने टिकटिंग में इंटरनेट का प्रयोग शुरू किया। आज यह प्रणाली इतनी लोकप्रिय है कि देश की ज्यादातर आबादी खिड़की की ओर रुख नहीं करती। देश में आज जितनी भी टिकटिंग की माँग है, उसका बड़ा हिस्सा (लगभग 88%) ऑनलाइन माध्यम से होता है।

भारतीय रेल का मोबाइल ऐप रेलवन यात्रियों के बीच बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। रेलवन ऐप की शुरूआत पिछले साल जुलाई में हुई थी। एक साल से कम समय में ही देशभर में अब तक 3.5 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं।

इस ऐप के लोकप्रिय होने के कई

कारणों में से सबसे बड़ा कारण यह है कि यह ऐप देश के आम आदमी को रेल संबंधी सभी जानकारियाँ तो देता ही है, टिकटिंग तथा अन्य सेवाओं से जुड़ी उनकी शिकायतों का भी निपटारा करता है।

आज जब आप अपनी टिकट बनाते हैं, तो रेलवन ऐप आपको यह बताता है कि आपकी वेटिंग में दिख रही टिकट कन्फर्म होगी या नहीं। टिकट के कन्फर्म होने की सटीक संभावना भी अब आपको एआई के माध्यम से रेलवन ऐप बताने लगा है। यह नई सुविधा इस साल की शुरूआत से ही लागू की गई है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। रेलवन ऐप पर वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53 प्रतिशत से बढ़कर अब 94 प्रतिशत तक पहुँच गई है।

रेलवन ऐप में इस तरह की कई एकीकृत एवं आधुनिक सुविधाएँ हैं, जो रेल संबंधी अन्य सभी सेवाओं को भी अपने में समाहित किए हुए हैं। जैसे - आरक्षित, अनारक्षित तथा प्लेटफॉर्म आदि विभिन्न प्रकार के टिकटों की बुकिंग, रद्दीकरण तथा रिफंड।

इसके साथ-साथ आपके मौजूदा टिकट की वेटिंग स्थिति की ताजा जानकारी, ट्रेन के आने-जाने का समय, ट्रेन की वर्तमान स्थिति, ट्रेन के आने-जाने का प्लेटफॉर्म, आपके कोच की स्थिति, तथा रेल मदद जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी रेलवन ऐप पर उपलब्ध हैं। अपनी यात्रा के दौरान आप रेलवन ऐप पर भोजन भी ऑर्डर कर सकते हैं। यह ऐप आपको यह विकल्प देता है कि आपकी सीट तक आपका मनपसंद खाना पहुँच सके। आरामदायक एवं सेवापरक सुविधाओं से लैस यह रेलवन ऐप तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

रोजाना इस ऐप के माध्यम से देशभर में 9.29 लाख टिकटें बुक हो रही हैं। इनमें 7.2 लाख टिकटें अनारक्षित तथा अन्य 2.09 लाख आरक्षित टिकटें हैं। अनारक्षित टिकटों में प्लेटफॉर्म टिकट भी शामिल है। एंड्रॉयड तथा आईओएस पर रेलवन ऐप को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। जहाँ 3 करोड़ 16 लाख लोगों ने इसे गूगल प्ले स्टोर से अब तक डाउनलोड किया है, वहीं 33.17 लाख लोगों ने इसे ऐपल फोन में डाउनलोड किया है।

देश में यात्रियों के लिए भारतीय रेल एक जीवन रेखा है। भारतीय रेल ने 2024झ्र25 में यात्रियों के टिकटों पर 60,239 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी। यह रेलवे पर यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 43% की छूट के बराबर है। दूसरे शब्दों में, यदि सेवा प्रदान करने की लागत 100 रुपये है, तो टिकट की कीमत केवल 57 रुपये है।

टीडीबी-डीएसटी का स्वच्छ परिवहन विजन के अंतर्गत स्वदेशी टाइप- सीएनजी सिलेंडरों के व्यावसायीकरण के लिए एनटीएफ एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को समर्थन

(जीएनएस)।

आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा परिवहन को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्वदेशी विनिर्माण को मजबूत करने के दृष्टिकोण के अनुरूप, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने "टाइप-क्स सीएनजी सिलेंडर के व्यावसायीकरण के लिए विनिर्माण सुविधा की स्थापना" नामक परियोजना के लिए दिल्ली स्थित मेसर्स एनटीएफ एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है।

इस परियोजना का उद्देश्य अत्याधुनिक फिलामेंट वाइंडिंग, ब्लो मोल्डिंग और उच्च दबाव परीक्षण तकनीकों का उपयोग करते हुए स्वदेशी रूप से विकसित टाइप-क्स कंपोजिट सीएनजी सिलेंडरों के उत्पादन और व्यावसायीकरण के लिए एक उन्नत विनिर्माण सुविधा स्थापित करना है। इस पहल से स्वच्छ परिवहन और उभरते ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए उन्नत गैस भंडारण प्रणालियों में भारत की घरेलू क्षमताओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

टाइप-क्स कंपोजिट सिलेंडर पारंपरिक स्टील सिलेंडरों का अगली पीढ़ी का विकल्प हैं और इनसे वजन में 75 प्रतिशत तक की कमी आती है जिससे वाहन की दक्षता बढ़ती है और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आती है। इन सिलेंडरों को जंग-रोधी पॉलीमर लाइनर, अनुकूलित सीएफआरपी लेआउट और उन्नत मैकेनिकल लॉकिंग सिस्टम के साथ डिजाइन किया गया है ताकि बेहतर सुरक्षा व टिकाऊपन सुनिश्चित हो और रिसाव, कंपन न हो। इसका डिजाइन 600 बार से अधिक का विस्फोट दबाव प्राप्त करता है, जो निर्धारित नियामक आवश्यकताओं से काफी अधिक है, जिससे मजबूत परिचालन सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

यह तकनीक एनटीएफ एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई है और इसे भारत के तेजी से बढ़ते सीएनजी मोबिलिटी इकोसिस्टम को सहयोग देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह परियोजना सरकार के सतत परिवहन, स्वच्छ ईंधन और उन्नत मोबिलिटी घटकों के घरेलू विनिर्माण की दिशा में किए जा रहे व्यापक प्रयासों के अनुरूप भी है।

प्रस्तावित संयंत्र स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल और उन्नत विनिर्माण प्रक्रियाओं का उपयोग करके उच्च दबाव वाले मिश्रित सिलेंडरों के लिए लागत-प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार उत्पादन प्रणाली का निर्माण करेगा। इस परियोजना से आयातित वस्तुओं के घरेलू उत्पादन, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता और देश में एक सुदृढ़ स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।

इस अवसर पर टीडीबी के सचिव श्री राजेश कुमार पाठक ने कहा कि उन्नत टाइप-क्स कंपोजिट सिलेंडरों का विकास और व्यावसायीकरण भारत के स्वच्छ परिवहन अवसंरचना और स्वदेशी विनिर्माण परितंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।

श्रीकृष्ण के चमत्कारों से ज्यादा उनके दिल की बात करती है 'कृष्णावतारम'

एक्शन और रोमांस ड्रामा के बाद अब बॉलीवुड में माइथोलॉजिकल फिल्मों की होड़ मच गई है। इस साल की सबसे चर्चित फिल्म 'रामायण' है लेकिन इसके पहले सिनेमाघरों में आज यानी 7 मई 2026 को 'कृष्णावतारम-पार्ट 1' रिलीज हुई है, जो सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक एहसास भी है।

क्या है 'कृष्णावतारम-पार्ट 1' की कहानी, जैसे श्रीकृष्ण की बांसुरी से निकली कोई मधुर धुन, जो सुनते ही

मन को कहीं दूर, वृंदावन की गलियों में ले जाती है। ये कहानी भगवान कृष्ण की है लेकिन यहां चमत्कारों से ज्यादा उनके दिल की बात होती है। राधा के साथ उनका प्रेम, रुक्मिणी की समर्पण भरी भावना और सत्यभामा का स्वाभिमान।

भगवान श्रीकृष्ण की खूबसूरत चित्र की कथा, हर रिश्ता एक अलग रंग भरता है और सब मिलकर एक खूबसूरत चित्र बनाता है। फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा कुछ कहना इसके मजा को मार सकता है। कहा जाए कि स्पॉइलर हो सकता है। ऐसे में फिल्म सिनेमाघर में ही देखना चाहिए।

फिल्म की स्टारकास्ट और उनकी एक्टिंग, एक्टिंग की बात करें तो फिल्म 'कृष्णावतारम-पार्ट 1' में सिद्धार्थ गुप्ता भगवान श्रीकृष्ण की भूमिका निभा रहे हैं।

विभाजनकारी मंसूबों का काम तमाम करना है.. देवबंद के फतवों का जिक्र कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधा निशाना

(जीएनएस)।

सहारनपुर. सहारनपुर के देवबंद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले देवबंद से हर बात के लिए फतवा जारी होता था. क्या खाना है और क्या नहीं इसके लिए भी फतवा जारी होता था. 2017 से पहले सहारनपुर की पहचान दंगों के लिए होता था. लेकिन आज सहरनपुयर की पहचान क्या है? आज प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है. कोई कर्फ्यू नहीं लगता. मुख्यमंत्री ने कहा कि तुष्टिकरण करने वालों से सतर्क रहना होगा. उन्होंने कहा कि विभाजनकारी मंसूबों का काम तमाम करना होगा .

इससे पहले मुख्यमंत्री ने देवबंद में 2,131 करोड़ रुपए लागत की लोक-कल्याणकारी परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि पहले दंगों से सहारनपुर की पहचान होती थी. जब देवबंद से फतवा जारी हुआ करतें थे और देश का माहौल गरमा जाता था. अब देश के विभाजनकारी मंसूबों को समाप्त करने का समय है. उन्होंने कहा कि विभाजन की राजनीति करने वाले देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

ना बंटने की अपील

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं। जब सरकार एक्टिव रहती है तो उसका काम जनता को दिखता है. तभी सरकार भी रिपीट होती है. उन्होंने कहा कि हमें बंटना नहीं है. टसहतीकरण और फतवे की राजनीति करने वालों से सतर्क रहना है. ये अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए जाति का सहारा लेते हैं और सनातन पर हमला होता है तो इनके मुंह पर फेविकोल लग जाता है.

तमिलनाडु में नया ट्विस्ट! थलापति विजय की मौज, भाजपा ने चल दी चाणक्य वाली चाल, कहीं की नहीं रहेगी कांग्रेस!

तमिलनाडु में तो थलापति विजय के दोनों हाथों में लड्डू है. एक्टर विजय की किसी भी कीमत पर सरकार बनकर रहेगी. कांग्रेस ही नहीं, अब तो भाजपा भी चाहती है कि टीवीके की ही तमिलनाडु में सरकार बने. मगर यहां एक ट्विस्ट है. भाजपा नहीं चाहती कि कांग्रेस संग थलापति विजय की सरकार बने. इसलिए अब भाजपा ने चाणक्य वाली चाल चल दी है. भाजपा ने एआईएडीएमके पर प्रेशर बनाया है कि वह एक्टर विजय की पार्टी टीवीके के साथ गठबंधन करे.

(जीएनएस)।

तमिलनाडु की सियासत में गजब ट्विस्ट आया है. थालापति विजय की टीवीके सरकार बनाने की कवायद में जुटी है. उसके पास बहुमत वाला नंबर नहीं है. इसलिए एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को अन्य साथियों की जरूरत है. थलापति विजय को सरकार बनाने के लिए कुल 118 विधायकों की जरूरत है. टीवीके के पास हैं 108. अब ऐसे में कैसे 118 के आंकड़े तक पहुंचा जाए, अभी इस पर मंथन जारी है. इस बीच तमिलनाडु के सियासी गेम में अचानक भाजपा की एंट्री हो गई है. सरकार वाली फ्रेम में अब तक भाजपा नहीं थी. मगर अब भाजपा ने एआईएडीएमके को धर्मसंकट में डाल दिया है. मगर एक्टर विजय के लिए तब भी खुशखबरी ही है.

जी हां, भाजपा के नए दांव से टीवीके चीफ थलापति विजय की चांद ही चांदी है. भाजपा अब चाहती है कि टीवीके की ही तमिलनाडु में सरकार बने. इसके लिए भाजपा तमिलनाडु में अपनी सहोयगी एआईएडीएमके को थलापति विजय की ळश्ङ के साथ गठबंधन के लिए जोर दे रही है. भाजपा के इस दांव से एआईएडीएमके धर्मसंकट में है. एआईएडीएमके पर टूट यानी विभाजन का खतरा मंडरा रहा है. उसे भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना जैसा खतरा महसूस हो रहा है.

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, तमिलनाडु रिजल्ट के बाद एआईएडीएमके (AIADMK) अपने सबसे गंभीर अंदरूनी संकट की ओर बढ़ती दिख रही है. एआईएडीएमके विजय की टीवीके के साथ गठबंधन को लेकर धर्मसंकट में है. पार्टी के भीतर इस बात पर गहरे मतभेद उभर आए हैं कि क्या थलापति विजय की पार्टी ह्यतमिलगा वेट्री कझगमह्ल (TVK) को गठबंधन सरकार बनाने में समर्थन दिया जाए या नहीं. सूत्रों का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भाजपा बहै.

भाजपा नहीं चाहती कि टीवीके और कांग्रेस का गठबंधन हो. इसके लिए भाजपा चाहती है कि एआईएडीएमके और टीवीके साथ मिलकर सरकार बनाए. इसकी वजह है भाजपा की जिद, सके तहत वह कांग्रेस को तमिलनाडु की सत्ता में आने से रोकना चाहती है.

क्यों भाजपा चाहती है टीवीके और AIADMK का गठबंधन

ख ु द एआईएडीएमके के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि भाजपा टॉप लीडरशिप इस बात से असहज है कि तमिलनाडु में कांग्रेस के सममर्थन से टीवीके की सरकार बन सकती है. वह भी ऐसी स्थिति में जब पड़ोसी राज्य केरल में कांग्रेस ने एक बार फिर से जोरदार वापसी की है. यही कारण है कि भाजपा नहीं चाहती कि तमिलनाडु की सत्ता में कांग्रेस की किसी भी तरह वापसी हो.

तमिलनाडु में सरकार का नंबर गेम समझिए

थलापति विजय की ळश्ङ के पास 108 सीटें हैं. बहुमत के लिए चाहिए 118 सीटें. मतलब बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें कम हैं. इसलिए तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए गठबंधन बनाना अब जरूरी हो गया है. ऐसे में भाजपा उन कोशिशों का समर्थन करती दिख रही है, जिनका मकसद अक्अऊट्ङ को विजय का साथ देने के लिए राजी करना है, ताकि कांग्रेस और वामपंथी दल को नई सरकार में आने से रोका जा सके.

भाजपा के दांव से एआईएडीएमके में धर्मसंकट

हालांकि, भाजपा के दांव से एआईएडीएमके में धर्मसंकट है. यह संकट तब और गहरा गया, जब मंगलवार रात एआईएडीएमके की वरिष्ठ नेता लीमा रोज मार्टिन ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि टीवीके और अक्अऊट्ङ के बीच बातचीत चल रही है. लीमा रोज मार्टिन लॉटरी किंग की पत्नी हैं. उनके बेटे पुडुचेरी से विधायक हैं और एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं. इसलिए एआईएडीएमके का एक खेमा चाहता है कि विजय की पार्टी संग गठबंधन हो. मगर एक खेमा चाहता है कि गठबंधन न हो. ऐसे में एआईएडीएमके में टूट का खतरा मंडरा रहा है.

विजय ने बुलाई अहम बैठक

इस बीच टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कड़गम के संस्थापक विजय ने सरकार गठन पर चर्चा के लिए आज यानी गुरुवार को यहां चुनाव जीतने वाले पार्टी के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई. यह बैठक सरकार बनाने के लिए टीवीके के बहुमत से कुछ सीट पीछे रहने की पृष्ठभूमि में हो रही है. कांग्रेस के पांच विजयी उम्मीदवारों ने टीवीके को समर्थन देने की पेशकश की है, लेकिन विजय की पार्टी को 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत नहीं मिल पा रहा है.

सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का होना जरूरी है और टीवीके ने 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में 108 सीट पर जीत हासिल की, जिनमें से विजय को अपनी जीती हुई दो सीट में से एक से इस्तीफा देना होगा. सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान टीवीके अपने विधायक दल के नेता का चुनाव भी कर सकती है.

यूपी में पशुओं के लिए विशेष 'भूसा बैंक', 26 लाख कुंतल से ज्यादा चारा जमा; सीएम योगी ने दिए अभियान तेज करने के निर्देश

(जीएनएस)।

लखनऊ। प्रदेश में बढ़ती गर्मी और आगामी महीनों में पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने व्यापक 'भूसा संग्रह अभियान' शुरू किया है। सरकार ने एक वर्ष के लिए अनुमानित 131.40 लाख कुंतल भूसे की आवश्यकता निर्धारित की है, जिसके सापेक्ष 60.99 लाख कुंतल भूसा संग्रह का लक्ष्य तय किया गया है। अब तक 26.78 लाख कुंतल भूसे का संग्रह किया जा चुका है, जो लक्ष्य का लगभग 43.9 प्रतिशत है।

इस अभियान के अंतर्गत दान एवं क्रय दोनों माध्यमों से भूसा संग्रह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक गो आश्रय स्थल पर अस्थायी एवं स्थायी भूसा बैंक स्थापित किए जाएं तथा स्थानीय किसानों से समन्वय कर भूसे की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

सकल भूसा संग्रह में ललितपुर प्रदेश में शीर्ष पर है, जहां लक्ष्य के मुकाबले 102.9 प्रतिशत भूसा संग्रह किया गया है। इसके बाद देवरिया (100.7 प्रतिशत) और गोरखपुर (96.1 प्रतिशत) का स्थान है। मऊ, आगरा, महाराजगंज, सहारनपुर और हरदोई जैसे जनपदों ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। वहीं सबसे कम प्रगति वाले जिलों में लखनऊ, कानपुर नगर, संभल और इटावा शामिल हैं, जहां संग्रह प्रतिशत अभी अपेक्षाकृत कम है। शासन स्तर से इन जिलों में अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

दान के माध्यम से भूसा संग्रह में महाराजगंज और जौनपुर आगे, दान आधारित भूसा संग्रह में अब तक 12.19 लाख कुंतल लक्ष्य के सापेक्ष 2.65 लाख कुंतल भूसा एकत्र किया गया है, जो 21.8 प्रतिशत प्रगति दशार्ता है। इस श्रेणी में महाराजगंज, जौनपुर, गाजियाबाद और रामपुर जैसे जिले अग्रणी बने हुए हैं। सरकार ने समाजसेवी संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, गोसेवकों और आम नागरिकों से भी इस अभियान में सहभागिता की अपील की है, ताकि गो आश्रय स्थलों में पशुओं के लिए चारे की कमी न हो।

पशुओं के लिए मानक युक्त आहार व्यवस्था लागू, मुख्यमंत्री के निर्देश पर गो आश्रय स्थलों में केवल गुणवत्ता युक्त और संतुलित पशु आहार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि पशु आहार केवल एफ एस एस ए आई मानकों एवं बी आई एस प्रमाणित आई एस 2023 के अनुरूप ही खरीदा जाए। पी सी डी एफ द्वारा उत्पादित 'पराग' पशु आहार को प्राथमिकता देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

इसके अलावा पैकिंग पर बैच नंबर, निर्माण एवं समाप्ति तिथि का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक गोवंश को प्रतिदिन न्यूनतम 500 ग्राम संतुलित पशु आहार उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

भूसा बैंक और टेंडर प्रक्रिया को मिली तेजी, प्रदेश में अब तक 1905 अस्थायी और 7285 स्थायी भूसा बैंक स्थापित किए जा चुके हैं। साथ ही भूसा टेंडर प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है। 14 जनपदों में टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि अन्य जिलों में प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा साइलेज टेंडर प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक गो आश्रय स्थल में पर्याप्त मात्रा में भूसा और पशु आहार उपलब्ध रहे, ताकि गर्मी और सूखे की स्थिति में भी पशुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

गो आश्रय स्थलों में गर्मी से बचाव के विशेष इंतजाम, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी गो आश्रय स्थलों पर स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त छाया, कूलर और पंखों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। स्थानीय किसानों के साथ समन्वय कर हरे चारे की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। सरकार का मानना है कि गो संरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, डेयरी विकास और कृषि आधारित जीवन प्रणाली का महत्वपूर्ण आधार है। इसी उद्देश्य के साथ प्रदेश सरकार भूसा संग्रह, पशु आहार और गो आश्रय प्रबंधन को मिशन मोड में आगे बढ़ा रही है।

भारत से परमाणु युद्ध की बात करना पागलपनः ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर बोली पाकिस्तानी सेना

(जीएनएस)।

इस्लामाबादः पाकिस्तानी सेना के प्रॉपगैंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन (ISPR) ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जीत का दावा किया और कश्मीर का राग अलापा। आईएसपीआर ने यह भी कहा कि भारत-पाकिस्तान में परमाणु युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने यह भी कहा कि अगर भी यह सोचता है कि दो परमाणु हथियार वाले पड़ोसी देशों के बीच युद्ध की कोई गुंजाइश है, वह पागल है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने मरका-ए-हक नाम का ऑपरेशन चलाया था। बाद में पाकिस्तान ने इसे ऑपरेशन बुन्यानुम मरसूस नाम दिया था।

ISPR ने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने संबोधित किया। उनके साथ नौसेना स्टाफ के डिप्टी चीफ (ऑपरेशंस) रियर एडमिरल शफाअत अली और वायु सेना स्टाफ के डिप्टी चीफ (प्रोजेक्ट्स) एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी भी मौजूद रहे। आईएसपीआर के जीडी अहमद शरीफ चौधरी ने मरका-ए-हक के दौरान मल्टी डोमेन ऑपरेशन चलाने का दावा किया और यहां तक कहा कि इसमें पाकिस्तानी सेना ने भारत को शिकस्त दी थी।

पाकिस्तान ने खुद को बताया ऑपरेशन सिंदूर का विजेता, उन्होंने कहा, "आज हम इस बात पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि क्या हुआ था... बल्कि हम मई 2025 से मई 2026 के बीच के समय पर ज्यादा ध्यान देंगे।" साथ ही यह भी जोड़ा कि वे इस संघर्ष के "रणनीतिक परिणामों" पर विस्तार से बात करेंगे। उन्होंने बताया कि 'मरका-ए-हक' के 10 रणनीतिक परिणाम सामने आए, जिनमें से पहला यह था कि पाकिस्तान को आतंकवाद के स्रोत के तौर पर पेश करने का भारत का नैरेटिव (कथा) पूरी तरह से दफ्न हो गया। उन्होंने कहा कि बिना किसी सबूत के यह

दिखाने की कोशिश की गई थी कि पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद फैलाया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना को एक साल बीत चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने जो सवाल उठाए थे, उनका जवाब अब तक नहीं मिला है।

भारतीय सेना का राजनीतिकरण और राजनीति का सैन्यीकरण खतरनाक है। आपने मरका-ए-हक के कुछ महीनों बाद उनके एयर चीफ मार्शल को यह कहते हुए सुना होगा। मुझे आज पता चला कि हमने भी कुछ विमान गिराए थे। यह सैन्य नेतृत्व का राजनीतिकरण है। आप अपने एडमिरलों, जनरलों और मार्शल को जोकर बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए।

लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उ्न्न्ह करढफ

पाकिस्तान ने खुद को बताया शांति दूत, पाकिस्तानी सेना ने पहलगाम आतंकी हमले में अपना हाथ होने का सबूत भी मांगा। आईएसपीआर के डीजी ने जहर उगलते हुए कहा, "सबूत कहां हैं?" उन्होंने आगे कहा, "कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता... असल में सबसे बड़े आतंकवादी तो आप खुद हैं। कोई उनकी बात नहीं सुनता, कोई उन पर भरोसा नहीं करता।" उन्होंने शेखी बघारते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा नतीजा यह था कि इस क्षेत्र में पाकिस्तान एक मुख्य सुरक्षा-स्थिरता लाने वाले देश के तौर पर मजबूत हुआ। उन्होंने कहा कि 'मरका-ए-हक' ने यह दिखा दिया कि तनाव को कौन नियंत्रित और हावी होकर संभाल रहा था।

प्रत्येक खेल संघ का मुख्य केंद्रबिंदु एथलीट कल्याण और एथलीट-केंद्रित शासन होना चाहिए : डॉ. मनसुख मांडविया

राष्ट्रीय खेल महासंघ सम्मेलन आगामी एशियाई, राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों की दिशा में एक समन्वित कदम है : केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया

राष्ट्रीय खेल महासंघ सम्मेलन में डॉ. मांडविया ने कहा, 'भारतीय खेल जगत से डोपिंग को जड़ से खत्म करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है'

आगामी अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की ओर भारत की प्रगति प्रदर्शन पर आधारित होगी, विज्ञान द्वारा संचालित होगी और मजबूत संघों पर टिकी होगी : खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे

भारतीय खेल का भविष्य एथलीटों, संघों और सरकारों के बीच मजबूत समन्वय पर निर्भर : डॉ. मांडविया

प्रविष्टि तिथिः 07 टअ 2026 5:24ढट ८ ढक्ह ऊै

केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल महासंघ सम्मेलन 2026 में भाग लिया, जिसमें भारतीय ओलंपिक संघ सहित 37 राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) के प्रतिनिधियों ने भारतीय खेल के भविष्य के रोडमैप और राष्ट्रमंडल खेल 2026, एशियाई खेल 2026 और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की तैयारियों पर विचार-विमर्श करने के लिए भाग लिया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मांडविया ने कहा, "राष्ट्रीय खेल महासंघ का यह सम्मेलन आगामी वैश्विक खेल आयोजनों के लिए भारत की तैयारियों की दिशा में एक समन्वित कदम है।"

खेल मंत्री ने दीर्घकालिक योजना, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, मजबूत खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे एथलीटों के लिए निरंतर समर्थन के माध्यम से भारत को एक अग्रणी खेल राष्ट्र में बदलने के सरकार के व्यापक विजन पर भी प्रकाश डाला।

संस्थागत सुधारों और सुशासन प्रणालियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. मांडविया ने कहा, "भारतीय खेल का भविष्य खिलाड़ियों, महासंघों और सरकारों के बीच मजबूत समन्वय पर निर्भर करता है।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महासंघों के भीतर शासन व्यवस्था एथलीट-केंद्रित रहनी चाहिए और उन्होंने अधिक पारदर्शिता, समय पर चुनाव, जवाबदेही और मजबूत संस्थागत तंत्र की मांग की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एथलीट कल्याण भारत के खेल इको-सिस्टम के केंद्र में रहे।

केंद्रीय मंत्री ने जागरूकता, शिक्षा और सख्त कानूनी उपायों के माध्यम से भारतीय खेल जगत से डोपिंग को खत्म करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

डॉ. मांडविया ने कहा, "भारतीय खेल व्यवस्था से डोपिंग को खत्म करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है।" उन्होंने महासंघों, प्रशिक्षकों और सहायक कर्मचारियों से देश में स्वच्छ और पारदर्शी खेल संस्कृति के निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान देने का आग्रह किया।

डॉ. मांडविया ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट और आगामी खेलो भारत मिशन जैसी पहलों के माध्यम से खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने के सरकार के व्यापक विजन पर भी प्रकाश डाला।

उन्होंने एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 में भारत के पदक जीतने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण, नियमित प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव, निजी क्षेत्र की भागीदारी, खेल लीग, अकादमियों और शासन सुधारों के महत्व पर जोर दिया।

इस सम्मेलन के दौरान, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के नियम और सुधार दिशानिर्देश पुस्तिका को भी औपचारिक रूप से जारी किया गया।

केंद्रीय खेल मंत्री ने अधिक जवाबदेही, पारदर्शी खिलाड़ी चयन प्रक्रियाओं और संघों के लिए निरंतर संस्थागत समर्थन के माध्यम से भारत की खेल संरचना को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

डॉ. मांडविया ने बताया कि सरकार खुली और निष्पक्ष चयन प्रणाली सुनिश्चित करने, प्रतिस्पर्धा के अवसरों को बढ़ाने, संघों के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव और एथलीटों, प्रशिक्षकों और शासन तंत्र में निवेश बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खडसे ने देश के लिए भविष्य के लिए तैयार खेल इकोसिस्टम के निर्माण में दीर्घकालिक योजना, खिलाड़ी सहायता प्रणालियों और वैज्ञानिक प्रशिक्षण पद्धतियों के महत्व पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि, "एशियाई गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक 2028 की ओर भारत की प्रगति प्रदर्शन पर आधारित होगी, विज्ञान द्वारा संचालित होगी और मजबूत महासंघों पर टिकी होगी।"

खेल सचिव श्री हरि रंजन राव ने भारत की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में सामूहिक जिम्मेदारी और दीर्घकालिक योजना के महत्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा, "जो राष्ट्र बड़े सपने देखता है, वह उससे भी बड़ी तैयारी करता है; आज की चचाएं 2036 के लिए भारत के खेल भविष्य को आकार देंगी।"

उन्होंने प्रतिस्पर्धा के अधिक अवसर, लीग और आधुनिक प्रशिक्षण प्रणालियों की आवश्यकता पर जोर देते हुए, भारत की वैश्विक खेल शक्ति बनने की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए महासंघों और हितधारकों के बीच समन्वित टीम वर्क का आ'ान किया।

इस सम्मेलन में भारत के विकसित हो रहे खेल संबंधी रोडमैप पर भी केंद्रित चचाएं हुईं, जिनमें खेलो इंडिया मिशन मेडल रणनीति, खेल सामग्री निर्माण को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक फिटनेस प्रोटोकॉल और एथलीट मूल्यांकन, डोपिंग विरोधी कानूनों को मजबूत करना, राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए तकनीकी क्रियाकलाप, एनएसजी अधिनियम 2025 के तहत शासन और अनुपालन, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करने और वैश्विक महासंघों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की भारत की महत्वाकांक्षा, साथ ही आगामी खेल आयोजनों के लिए रणनीतिक तैयारी शामिल हैं।

सम्मेलन में उपस्थित विभिन्न महासंघों के प्रतिनिधियों ने सभी सत्रों में सक्रिय रूप से भागीदारी की और चचाओं में हिस्सा लिया।

बिना चुनाव लड़े मंत्री बने दीपक प्रकाश के पास कैश की कमी

(जीएनएस)।

बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार गुरुवार को संपन्न हो गया। इस नई कैबिनेट में कुल 35 मंत्रियों को जगह दी गई है, जिसमें सबसे चर्चित नाम दीपक प्रकाश का है। आरएलएम (RLM) चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने एक बार फिर बिना किसी सदन (विधानसभा या विधान परिषद) का सदस्य रहे मंत्री पद की शपथ ली है।

राजनीतिक गलियारों में उनके दोबारा मंत्री बनने को लेकर जितनी चर्चा है, उतनी ही चर्चा उनकी 'करोड़पति' नेटवर्थ की भी हो रही है। आइए जानतें हैं मंत्री (दीपक प्रकाश) के पास कितनी धन-दौलत है?

हलफनामे में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा- 25 दिसंबर 2025 को दाखिल किए गए आधिकारिक हलफनामे के अनुसार, दीपक प्रकाश करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। वैशाली जिले के मूल निवासी दीपक प्रकाश की कुल अचल संपत्ति 4 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उनके गृह जिले वैशाली में है, जिसमें जंदाहा स्थित 3 करोड़ मूल्य की गैर-कृषि भूमि और एक तीन मंजिला इमारत शामिल है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है।

दीपक प्रकाश के निवेश पोर्टफोलियो में सबसे चौंकाने वाली बात उनके और उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा के पास मौजूद आभूषण हैं। हलफनामे के मुताबिकः

सोना दीपक प्रकाश के पास 15 ग्राम सोना है, जबकि उनकी पत्नी के पास 500 ग्राम (आधा किलो) सोना है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 60 लाख रुपए है।

चांदी : साक्षी मिश्रा के पास 5 किलो चांदी भी है, जिसका मूल्य करीब 10 लाख रुपए बताया गया है।

नकदी और बैंक बैलेंस : कैश के मामले में दोनों के पास मात्र 10-10 हजार रुपए हैं, लेकिन अलग-अलग बैंक खातों में दीपक के पास करीब 6.94 लाख और उनकी पत्नी के पास 1.58 लाख रुपए जमा हैं।

दीपक प्रकाश की लग्जरी लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल की बात करें तो मंत्री जी के पास 2019 मॉडल की फोर्ड फ्रीस्टाइल कार और 2021 मॉडल की बजाज मोटरसाइकिल है। इसके अलावा, उन्होंने और उनकी पत्नी ने एलआईसी की पॉलिसियों में भी निवेश किया है, जिसकी कुल वैल्यू लगभग 8.6 लाख रुपए से अधिक है।

दीपक के सामने संवैधानिक चुनौती

दीपक प्रकाश की यह नियुक्ति जितनी प्रभावशाली है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। चूंकि वह अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें 6 महीने के भीतर विधायक या विधान पार्षद बनना अनिवार्य होगा। अगर वह 6 महीने में सदन के सदस्य नहीं बनते हैं, तो उनका मंत्री पद तो जाएगा ही, साथ ही उन्हें भविष्य में मिलने वाली पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाओं से भी हाथ धोना पड़ सकता है।

इससे पहले भी वह नवंबर 2025 में मंत्री बने थे, लेकिन सरकार बदलने के कारण 4 महीने में ही पद चला गया था। इस बार उनके पास खुद को साबित करने और सदन की सदस्यता हासिल करने की बड़ी चुनौती होगी।

कितने पढ़े-लिखें हैं दीपक प्रकाश?

राजनीति में कदम रखने से पहले दीपक प्रकाश ने तकनीकी क्षेत्र में अपना करियर बनाया था। उन्होंने साल 2011 में 'मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' से कंप्यूटर साइंस में बी.टेक (इ.ळीं) की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने लगभग चार साल तक आईटी (क्ळ) सेक्टर में काम किया। राजनीति में एक्टिव होने से पहले वह विदेश में भी रहे और इसके बाद उन्होंने भारत लौटकर अपने पिता उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 'आरएलएम' (फछट) में जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कीं।